

भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2617

जिसका उत्तर मंगलवार, 09 दिसम्बर, 2014 को दिया जाना है

कलपुर्जों का विनिर्माण

2617. श्री एन. के. प्रेमचंद्रन:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने मोटर वाहन कंपनियों द्वारा कलपुर्जों के पर्याप्त विनिर्माण हेतु कोई शर्तें निर्धारित की हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार के संज्ञान में आया है कि ऑटोमोबाइल कंपनियों द्वारा कलपुर्जों का उत्पादन न किए जाने के कारण वाहनों की मरम्मत के लिए कलपुर्जे उपलब्ध नहीं हैं यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं;
- (ग) क्या उन कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है जो कलपुर्जों के पर्याप्त मात्रा में निर्माण में असफल हो गई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या सरकार ने इस संबंध में विभिन्न संगठनों द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर कोई कार्रवाई की है; और
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

**भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री जी. एम. सिद्धेश्वर)**

(क) से (ग): जी, नहीं। ऑटो कंपोनेन्ट्स और कलपुर्जों के विनिर्माण से न केवल देश की घरेलू आवश्यकताएं पूरी होती हैं, अपितु इन कंपोनेन्ट्स का काफी मात्रा में निर्यात भी किया जाता है। सरकार ऑटोमोटिव मिशन प्लान 2006-16, यूनिडो-एकमा क्लस्टर कार्यक्रम आदि जैसी योजना के तहत उच्च गुणवत्ता वाले कंपोनेन्ट्स के उत्पादन के लिए ऑटोमोबाइल कंपोनेन्ट्स विनिर्माण को सक्रिय रूप से बढ़ावा देती है और प्रोत्साहित करती है।

(घ) और (ङ): सरकार को इस संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।
